

राजस्थान सरकार

प०कः- 6(9)राज-6/96पार्ट | १७

जयपुर, दिनांक:- १७.१०.२००५

1. समस्त जिला कलेक्टर, राज०।
 2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
 3. निदेशक, स्थानीय निधि अकोक्षण विभाग।

विषय:- शहरी निकाय क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की 40 प्रतिशत हिस्सा राशि राज्य सरकार के कोष में जमा कराने बाबत।

प्रायः यह देखने में आया है कि शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित 90 बी के लिए राजस्व विभाग द्वारा घोषित सक्षम अधिकारियों द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ जो रूपान्तरण किया जा रहा है, उसमें राज्य सरकार के हिस्से की 40 प्रतिशत राशि, शहरी निकाय द्वारा वसूल कर ली जाती है, लेकिन राज्य सरकार के मद में समय पर जमा नहीं करायी जाती। अतः समस्त स्थानीय निकायों को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके शहरी निकाय क्षेत्रों में कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ जो रूपान्तरण किया है उसमें राज्य सरकार के हिस्से की 40 प्रतिशत राशि तुरन्त प्रभाव से राज्य सरकार के कोष में जमा करवा कर एक माह में पालना रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करें। निदेशक, स्थानीय निधि अकेंक्षण विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि स्थानीय निकायों का अकेंक्षण करते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि उन्होंने वसूल की गई राशि का 40 प्रतिशत राजकोष में जमा कराया है अथवा नहीं। पूर्व के वर्षों की यदि राशि जमा नहीं कराई गई है तो उसका अकेंक्षण पैरा बनाया जावें और राशि राजकोष में जमा कराई जावें। यदि स्थानीय निकायों द्वारा उक्त राशि जमा नहीं कराई जाती है तो स्थानीय निधि अकेंक्षण विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय निकायवार बकाया राशि की सूचना इस विभाग को व वित्त विभाग को प्रेषित करें ताकि वित्त विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकाय को देय अनुदान राशि में से कटौती की जा सके।

प्रतिलिपि :-

१. शासन सचिव,वित्त(व्यय) विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(क०१०अग्रवाल) १७.५.०५
उप शासन सचिव

~~शासन अम सचिव, राजस्व~~ 17-X-05